

## न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास- पीयूष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या -61/2021  
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर - 2021/87

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोजेण्ट
पांचाराम पुत्र हरदीनराम जाति जाट निवासी आकेली ए तहसील मेड़ता जिला नागौर राजस्थान		नायब तहसीलदार, मेड़तासिटी, जिला नागौर, राजस्थान

### उपस्थिति:-

- अपीलान्ट की ओर से वकील श्री भंवरलाल सारस्वत।
- रेस्पोजेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

### निर्णय

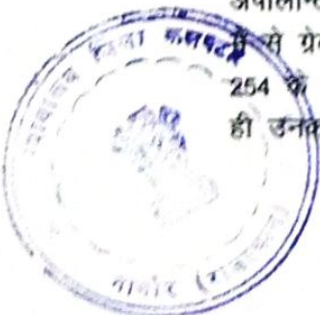
दिनांक 02/05/2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार मेड़तासिटी द्वारा मुकदमा नम्बर-5/2021 सरकार बनाम पांचाराम अधीन धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.07.2021 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 211 रकबा 0.02 हैक्टर वाके मौजा आकेली ए में अपीलान्ट का संवत 2078 में अतिक्रमण बताकर अपीलान्ट को नोटिस दिया। जिसका जबाब अपीलान्ट ने दिनांक 06.07.2021 को प्रस्तुत कर दिया। उसके पश्चात दिनांक 22.07.2021 को नायब तहसीलदार मेड़तासिटी द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व रेकॉर्ड के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 19 व 19/1702 अपीलान्ट के खातेदारी के खेत है, उसके चिपते ही खसरा नम्बर 211 गैर मुमकिन रास्ता है। इस रास्ते के चिपते ही खसरा नम्बर 254 व 253 अन्य व्यक्ति के खातेदारी के खेत है। जिनका रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण है, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा उन खेतों का न नाप किया और न ही उनके विरुद्ध रास्ते पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। सरपंच के दबाव में आकर आसी रजिशवश मात्र अपीलान्ट को अतिक्रमी बताकर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की गई। जबकि अपीलान्ट की माठ वर्षों से कायम है। अपीलान्ट ने संवत 2078 में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया। अपीलान्ट के खेत से खसरा नम्बर 253 व खसरा नम्बर 254 मौजा आकेली की लगभग 7 फुट नीचे है और उन खातेदारों का रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण है, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा उनको किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया, न उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की। जिससे यह परिचायक है कि मात्र अपीलान्ट को परेशान करने की नियत से और उसे नुकसान पहुंचाने की नियत से आपसी रजिस्टर से दुराग्रह से प्रसित होकर सरपंच ने पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध कार्यवाही करवायी है।

अपीलान्ट ने दिनांक 06.07.2021 को ही जबाब प्रस्तुत कर दिया जिसमें समस्त तथ्यों का उल्लेख किया और नायब तहसीलदार से निवेदन किया कि सरपंच अशोक गोलिया को मतदान अपीलान्ट द्वारा नहीं करने से उसने रजिस्टर से यह कार्यवाही करवाई है और जबकि अपीलान्ट के खेत से ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाना चाहता है। जबकि रास्ते के चिपते ही खसरा नम्बर 253 व 254 के खातेदारों का अतिक्रमण है, जो उसके पक्ष के लोग है उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की, न ही उनको बेदखल करना चाहता है। सरपंच इस हटधर्मिता पर अडा हुआ है कि खसरा नम्बर 253



कलक्टर, नागौर

व 254 मौजा आकेली ए के खातेदारों के कब्जे यथावत रहें और सड़क अपीलान्ट के खेत में से ही निकलेगी। जबकि अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार जी मेड़तासिटी से निवेदन किया कि आप टीम गठित कर मुस्तकिल पोईंट से नाप करवाकर रास्ते का सीमाकन करवाकर जिन-जिन व्यक्तियों का अतिक्रमण है, उनका अतिक्रमण हटावे व मेरा भी अतिक्रमण निकलता है तो मैं हटाने के लिए तैयार हूँ, परन्तु नायब तहसीलदार ने पटवारी हल्का से पुनः रिपोर्ट मांगी, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा पुनः किसी तरह का मौके पर अपीलान्ट के समक्ष मुस्तकिल पोईंट से नाप नहीं किया और घर बैठे ही वापिस दिनांक 20.07.2021 को मनगढ़त तथ्यों के आधार पर ही रिपोर्ट पेश कर दी, जो न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। न्याय का सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश करने से पूर्व उसे सुनवाई का मौका देना चाहिए और समभाव से निष्पक्षता से निर्णय करना चाहिए, लेकिन नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की पुनः रिपोर्ट जो अवलोकन से ही निष्पक्ष प्रतीत नहीं होती और न ही उसमें किसी तरह का नाप चौप करने का उल्लेख किया है, न ही नाप चौप किया है, ऐसी स्थिति में मात्र अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नियत से ही अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने में भूल की है, जो आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के खेत का प्रशिक्षित पटवारी या तहसीलदार या उप तहसीलदार या रेवेन्यू निरीक्षक क्वी टीम गठित कर मौके का यानि अपीलान्ट के खेत का मुस्तकिल पाईंट से नाम करवाया जाता है और रास्ता की भूमि का नाप करवाया जाता है तो वास्तविक स्थिति सामने आ जायेगी और टी के द्वारा अगर अपीलान्ट का कब्जा पाया जाता है तो अपीलान्ट अविलम्ब कब्जा हटाने के लिए तैयार है। परन्तु अपीलान्ट का खेत मौके पर कम है उसने अतिचार नहीं किया और इस आदेश की पालना में उनकी बाड़ हटा दी जाती है तो उनके संवैधानिक अधिकारों की हत्या होगी और उनक़े हितों पर भारी कुठाराघात होगा। अधिनस्थ न्यायालय ने जो बिना किसी शहादत सबूत और विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना आदेश पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के खेत का मुस्तकिल पोईंट से नाप करवाकर अपीलान्ट के विरुद्ध कब्जा पाया जाता है तो अतिक्रमी मानकर कार्यवाही करना न्याय संगत था, इसलिए अधिनस्थ न्यायालय को टीम गठित कर अपीलान्ट के खेत व रास्ता का सही सीमा ज्ञान करवाने का कथन करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 22.07.2021 खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने रेस्पोंडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पटवारी हल्का कात्यासनी की रिपोर्ट दिनांक 14.06.2021 एवं तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी कात्यासनी से पुनः रिपोर्ट चाही गई, जिसमें भी पटवारी कात्यासनी द्वारा अपीलान्ट का उक्त वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण होना बताया है। हस्तगत अपील में भी अपीलान्ट के निवेदन पर प्रकरण वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के अतिक्रमण के संबंध में तहसीलदार मेड़ता से रिपोर्ट चाही गई, जिसके कम में तहसीलदार मेड़ता द्वारा पत्रांक-1777 दिनांक 22.11.2021 से अपनी रिपोर्ट मय सीमाज्ञान रिपोर्ट भिजवाई है, जिसके अनुसार भी अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है। सीमाज्ञान के समय अपीलान्ट स्वयं मौका पर उपस्थित था, परन्तु सीमाज्ञान रिपोर्ट पर अपीलान्ट ने अपने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर स्पष्ट रूप अतिक्रमण साबित होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ग्राम आकेली "अ" के खसरा नम्बर 211 रकबा 0.02 हैक्टयर गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा मिट्टी का पाल व बाड़ बनाकर नाजायज कब्जा किया है, जो पटवारी हल्का कात्यासनी की रिपोर्ट दिनांक 14.06.2021 जिस पर निरीक्षक भू अभिलेख के भी हस्ताक्षर है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया है। इसके पश्चात अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब प्रस्तुत किया। उक्त जबाब के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का कात्यासनी से तथ्यात्मक जो रिपोर्ट चाही, जिस पर पटवारी कात्यासनी द्वारा दिनांक 20.07.21 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर खसरा



कलेक्टर, जायपुर

नम्बर 211 गै.मु. रास्ता का जो नाप होता है वह मौके पर खुला नहीं होना तथा राजस्व रेकॉर्ड के नक्शे व वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार अपीलान्ट का अतिक्रमण होना बताया है।

अपीलान्ट के निवेदन पर न्यायालय हाजा द्वारा आदेशिका दिनांक 01.11.21 अनुसार प्रकरण में वादग्रस्त गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अपीलान्ट के द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया है अथवा नहीं के संबंध में अपीलान्ट की उपस्थिति में मौका देखकर रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार मेड़ता को निर्देशित किया गया। उक्त संबंध में तहसीलदार मेड़ता द्वारा अपने पत्रांक-भूअ./सीमाज्ञान/2021/1777 दिनांक 22.11.2021 के साथ सीमाज्ञान रिपोर्ट भिजवाते हुए अवगत कराया है कि "अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजस्व टीम का गठन कर स्वयं द्वारा मौके पर दिनांक 19.11.21 को सीमाज्ञान किया गया। खसरा संख्या 211 गै.मु. रास्ता के सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी पांचाराम का बिंदु संख्या B पर खसरा संख्या 211 में अतिक्रमण पाया गया जो कि 6x70 मी. त्रिभुजाकार स्थिति है, जो नजरिये नक्शा में बिंदु संख्या B, G, H से दर्शाया गया है, जो लगभग 0.02 है। भूमि पर है। अपीलार्थी स्वयं मौके पर उपस्थित था, परन्तु सीमाज्ञान रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया।" इस प्रकार उक्त रिपोर्ट से भी अपीलान्ट का वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण स्पष्ट रूप से साबित है।

इस प्रकार पटवारी द्वारा प्रस्तुत दोनों रिपोर्टों एवं तत्पश्चात सीमाज्ञान रिपोर्ट से अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि रास्ते की सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया जाना साबित होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मेड़ता को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।



(पीयूष) समारिया  
जिला कलेक्टर, नागौर  
कलेक्टर, नागौर